सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-1 | 7 से 21 जनवरी, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

अप्रतिरोध्य और अपराजेय है नवम्बर क्रांति का पैगाम

–प्रभास घोष

(17 नवम्बर 2017 को महान नवम्बर क्रांति शताब्दी वर्ष का समापन समारोह एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया गया था। वहाँ यह भाषण पार्टी के महासचिव कॉ. प्रभास घोष ने दिया था जिसे उन्होंने स्वयं ही संपादित किया है। अनुवादन तथा भावों की अभिव्यक्ति में हुई त्रुटि के लिए सर्वहारा दृष्टिकोण का सम्पादक मण्डल जिम्मेदार होगा।)

कॉमरेड अध्यक्ष, मेरे घनिष्ट मित्र और बासद (मार्क्सवादी) बांग्लादेश के महासचिव और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉ. मुबीनुल हैदर चौधरी और दोस्तो,

आप जानते हैं कि महान मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग के योग्य शिष्य और इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिंतनकार कॉ. शिवदास घोष ने हमारे देश में मार्क्सवाद-लेनिनवाद और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को शान से बुलंद करते हुए और महान नवम्बर क्रांति के रास्ते का अनुसरण करते हुए, पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर समाजवादी क्रांति सम्पन्न करने का कार्य पूरा करने के लिए कष्टसाध्य संघर्ष के माध्यम से एसयूसीआई (सी) की स्थापना की थी। इसलिए नवम्बर क्रांति के शताब्दी वर्ष को मनाना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और जरूरी है। हमारी पार्टी द्वारा नवम्बर क्रांति शताब्दी वर्ष मनाने के लिए वर्षभर कार्यक्रम किए गए। शुरूआत 7 नवम्बर 2016 को मावलंकर हाल, दिल्ली से की गई थी। सालभर चलने वाले इस कार्यक्रम में हमारे हजारों कॉमरेडों द्वारा पूरे देश भर में, विभिन्न गांव-शहरों, मिल-फैक्ट्रियों, गली-मौहल्लों में मजदूर-किसानों, मध्यम वर्गीय लोगों, छात्र-नौजवानों और महिलाओं के बीच नवम्बर क्रांति के महत्व को समझाने के लिए असंख्य बैठकें, विचार-गोष्ठियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसलिए कि नवम्बर क्रांति ने एक उन्नत नई सभ्यता का निर्माण किया था। यह 70 वर्ष तक बरकरार रही। नवम्बर क्रांति की बात सुनने से ही साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों की रीढ़ में कम्पन पैदा हो जाती है और वे भय से थर-थर कांपने लगते हैं। इसलिए, उन्होंने नवम्बर क्रांति को इतिहास के पन्नों से ही मिटा डालने और इसकी गौरवमयी छवि को धूमिल करने का भरसक प्रयास किया है। वर्तमान पीढ़ी के बहुत से लोग इस ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति के तथ्य से अनभिज्ञ हैं। अपने स्वार्थ में उनकी इस घृणित चाल के बावजूद भी पूरे देश में जब हम नवम्बर क्रांति का प्रचार कर रहे थे तो हमने पाया कि नवम्बर क्रांति का संदेश अप्रतिरोध्य और अजेय है। आज की यह विशाल सभा इस बात को और भी पुख्ता करती है। मैं पूरे मंच की ओर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ जो खराब मौसम की मार झेलते हुए भी इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश बांग्लादेश से हिस्सा लेने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं।

नवम्बर क्रांति ने सिद्ध कर दिखाया कि मानव के द्वारा मानव का शोषण किया जा सकता है खत्म

मानव सभ्यता के विभिन्न युगों में हजारों साल से ही–आदिम युग के बाद से ही समाज वर्ग-विभाजित रहा है, पहले दास-दासप्रभु व्यवस्था, उसके बाद सामंतवाद में और फिर पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग-विभाजन रहा है–शोषित-पीड़ित लोगों ने आँखों में आँसू भर कर बार-बार यह सवाल किया है कि क्या कभी उनके दुख-तकलीफों का अंत होगा? क्या कभी शोषण-दमन का खात्मा हो पायेगा? शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था क्या कभी बदलेगी? महान लेनिन और उनके योग्य क्रांतिकारी सहयोद्धा महान स्टालिन ने मार्क्सवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए नवम्बर क्रांति को सफल करके इन सवालों का जवाब प्रदान किया। हाँ, समाज से वर्ग शोषण-शासन को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है यदि शोषित जनता क्रांतिकारी विचारधारा के तहत संगठित होकर और दृढ़तापूर्वक सिर ऊँचा उठा कर एक क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन गठित करें –नवम्बर क्रांति ने इसे यथार्थ रूप से सिद्ध किया है।

दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों ने की थी नवम्बर क्रांति की प्रशंसा

नवम्बर क्रांति ने 20वीं शताब्दी में पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया था। जहाँ एक तरफ बहुत से देशों के शोषित-पीड़ित लोगों को नवम्बर क्रांति ने प्रेरित किया, वहीं दूसरी तरफ नवम्बर क्रांति ने विश्वभर में साम्राज्यवादियों और पूंजीवादियों को भयभीत कर दिया था। नवम्बर क्रांति पिछली शताब्दी की एक महान और युगांतकारी घटना रही है। 20वीं शताब्दी में नवम्बर क्रांति ने न केवल रूस में शोषणमूलक व्यवस्था को उखाड़ फेंका और दूसरे-दूसरे देशों के शोषित वर्ग को प्रेरित किया, बल्कि इस क्रांति के द्वारा समाजवाद कायम करने का भी महत्वपूर्ण काम किया गया। उसने मानवीय सभ्यता के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, अमरीकी साम्राज्यवाद समेत सभी साम्राज्यवादी शक्तियों का आखेट स्थल रहा है। अधिकतर देश इनके उपनिवेश या अर्ध उपनिवेश थे। नवम्बर क्रांति के बाद स्थापित रूसी समाजवाद इन औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत था। यही वजह थी कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय नेताओं जैसे चीन के सुनयात सेन, इंडोनेशिया के सुकरणो तथा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मण्डेला ने बार-बार समाजवाद का अभिनंदन किया। पहली बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने हरीपुरा कांफ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा था कि 'पूरा विश्व दो खेमों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कक्षा-1 से पास-फेल प्रणाली पुनः अविलम्ब लागू करने की मांग पर
एआईडीएसओ का संसद मार्च

नई दिल्ली : प्रदर्शन करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता

नई दिल्ली। कक्षा-1 से पास-फेल प्रणाली पुनः अविलम्ब लागू करने की मांग पर 21 दिसम्बर को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन (एआईडीएसओ) द्वारा एक संसद मार्च का आयोजन किया गया। इस संसद मार्च में देश के कई राज्यों से सैकड़ों छात्र- छात्राओं ने हिस्सा लिया।

यह मार्च रामलीला मैदान के नजदीक स्थित गुरु नानक नेत्र चिकित्सालय से शुरू कर टॉलस्टाय मार्ग व बाराखम्बा रोड होते हुए संसद मार्ग की ओर रवाना हुआ। लेकिन पुलिस द्वारा बैरीकैड लगाकर जुलूस आगे जाने से रोक दिया गया। मार्च एक विरोध सभा में तब्दील हो गया। विरोध सभा की अध्यक्षता एआईडीएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल साईं ने की। सभा को एआईडीएसओ के कार्यालय सचिव चंचल घोष, मध्य प्रदेश से सचिन जैन, दिल्ली से प्रशान्त कुमार, हरियाणा से हरीश सैनी ने संबोधित किया। सभा का संचालन एआईडीएसओ के अखिल भारतीय काउंसिल सदस्य राहुल सरकार ने संबोधित किया। सभा के दरम्यान

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

में बंट चुका है–एक है समाजवादी खेमा और दूसरा है साम्राज्यवादी पूंजीवादी खेमा। यह समाजवाद ही हमारी प्रेरणा है।' इस देश के सभी क्रांतिकारियों ने इस मत को साझा किया है। सोवियत समाजवाद ने साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ होने वाले सभी स्वतंत्रता संग्रामों को मदद पहुंचाई थी। नहीं तो साम्राज्यवादी ताकतें आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। केवल समाजवाद की वजह से ही विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन सफल हुए।

स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन ने की थी फासीवाद से मानवजाति की रक्षा

ये सच है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश हुकूमत कमजोर पड़ गई थी। आजाद हिंद फौज की अग्रगति तथा मुम्बई में नौसेना विद्रोह और उससे पहले 1942 में हुई अगस्त क्रांति ने स्थिति और भी अधिक अनुकूल बना दी थी। इसके अलावा पूर्वी यूरोप और चीन में समाजवाद की विजय यात्रा के साथ-साथ वियतनाम के मुक्ति-संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों को वस्तुत: हिला कर रख दिया था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ के साथ समझौता किया। क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो और चे-गुएरा भी नवम्बर क्रांति से बहुत प्रभावित थे। अफ्रीका के पैट्रिस लुमुंबा ने भी नवम्बर क्रांति से प्रेरणा प्राप्त की थी, जिनकी अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ साम्राज्यवादी चाहते थे कि ये औपनिवेशिक-अर्धऔपनिवेशिक देश स्वतंत्रता के बाद भी इतने विकसित न हो जाएं कि ये पूर्णत: आत्मनिर्भर हो जाएं। उस समय पर इन नवोदित देशों को समाजवादी खेमा उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। भारत ने भी एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए समाजवादी खेमे से हर प्रकार की सहायता प्राप्त की थी। यह वह समय था जब ये विकासशील राष्ट्रीय देश साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से बाहर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समाजवादी खेमे की सहायता से गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब जर्मनी, इटली व जापान का फासीवादी गठजोड़ समस्त विश्व को तबाह करने पर तुला हुआ था। उसने फ्रांस समेत यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और इंग्लैण्ड को परास्त करने ही वाला था। जापानी सेनाएं मयांमार तक बढ़ चुकी थी और उन्होंने चीन पर कब्जा कर लिया था। जब पूरा विश्व बर्बादी की कगार पर था, केवल स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन की लाल सेना ही थी जिसने रक्षक की भूमिका निभाई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस काल में हमारे देश की तथा विश्व की सभी सम्माननीय हस्तियाँ जैसे रोमाँ रोलाँ, बर्नार्ड शा, आइन्स्टीन आदि सिर पर मंडरा रहे इस खतरे को नाकाम करने की उम्मीद सिर्फ सोवियत रूस से ही कर रहे थे। रवीन्द्रनाथ उस समय मृत्यु शैया पर थे। उस समय एक जाने-माने वैज्ञानिक श्री प्रशांतचन्द्र महलनोवीस उनकी देखरेख कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर हर रोज लाल सेना की अग्रगति के विषय में पूछते थे। एक दिन उन्हें बताया गया कि लाल सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह सुनकर वे बहुत विचलित हो गए और उन्होंने अखबार को फेंक दिया। जिस दिन उनका एक ऑपरेशन हुआ, उसी दिन जब महलनोवीस ने उन्हें बताया कि लाल सेना आगे बढ़ रही है, उसके तुरंत बाद ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने कहा कि वे अवश्य विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि एक मात्र लाल सेना ही फासीवादी दुष्ट ताकतों को हराकर विजय प्राप्त कर सकती है। वास्तव में सच्चाई भी यही थी। अगर सोवियत संघ एवं सोवियत समाजवाद नहीं होता और यदि साहसी स्टालिन के नेतृत्व में यह युद्ध नहीं हुआ होता, तो विश्व का इतिहास कुछ और ही होता। यह केवल हमारा दावा नहीं है। साम्राज्यवादी कर्णधारों, चर्चिल और रूजवैल्ट ने भी सोवियत यूनियन की गौरवपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था। इस तरह मानव इतिहास में सोवियत यूनियन ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी।

हमारे देश की जानी-मानी हस्तियों ने भी किया था सोवियत समाजवाद का समर्थन

आप लोगों ने हमारी पार्टी के मुखपत्र में पढ़ा है कि रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र, प्रेमचंद, नजरूल, सुब्रह्मण्यम भारती और ज्योतिप्रसाद से शुरू करके मुलकराज आंनद, कृश्नचंद्र और इकबाल तक देश के सभी अग्रिम पंक्ति के लेखकों ने नवम्बर क्रांति की बहुत सराहना की थी। शरतचंद्र ने मजदूर वर्ग की क्रांति का आह्वान करते हुए अपने उपन्यास 'पथ के दावेदार' की रचना की थी। इस उपन्यास पर ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि यह उपन्यास बोल्शेविक विचारों को फैला रहा है। नजरूल ने साम्यवाद और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की स्तुति करते हुए कविताएं रची थी। इसी समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जाने-माने नेताओं जैसे विपिनचंद्र पाल, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने भी समाजवाद की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने समाजवाद का अभिनंदन किया था और जवाहरलाल नेहरू ने भी नवम्बर क्रांति की बहुत सराहना की थी। यहाँ तक कि गाँधीजी ने भी समाजवाद की भूरी-भूरी प्रशांसा की है। इनमें से कोई भी कम्युनिस्ट नहीं था। रोमाँ रोलाँ, बर्नार्ड शां और आइन्स्टीन समाजवाद की प्रशंसा करते हुए भावुक क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने पाया कि फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती राजशाही के शासन का खात्मा कर बुर्जुआ लोकतंत्र की स्थापना की थी। समानता-स्वतंत्रता-भाईचारे और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद के जिस नारे को बुलंद करके उदयीमान बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में भूदासों ने बुर्जुआ जनवादी क्रांति की थी, जिसने सामंती राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र की माँग उठाई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में 'लोगों के द्वारा', 'लोगों की' और 'लोगों के लिए' सरकार का नारा बुलंद किया था। विश्वभर में एक नई लहर का संचार हुआ था। लेकिन बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के अटल रास्ते का अनुसरण करते हुए छोटी पूंजी बड़ी पूंजी में और एकाधिकारी पूंजी में तब्दील हो गई और पूंजीवाद के विकास के प्रारंभिक काल में पुरातन सामंती व्यवस्था का खात्मा करने के लिए बुर्जुआ वर्ग ने जो प्रगतिशील भूमिका निभाई थी, वह खत्म हो गई। परिणामस्वरूप पूंजीवाद प्रतिक्रियाशील हो गया और बुर्जुआ वर्ग ने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और मानवतावाद के झण्डे को नीचे फेंक दिया। इस प्रकार बुर्जुआ लोकतंत्र के मूल्यों को स्वयं बुर्जुआ वर्ग ने ही अपने पैरों तले रौंद दिया। आज हम साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में कुछ पूंजीपति घरानों और लाखों-लाख गरीब लोगों के बीच बहुत बड़ा भयंकर अंतर पाते हैं। आर्थिक विषमता और वंचना भयावह रूप से बढ़ रही है। बीबीसी के अनुसार 1 प्रतिशत अमीरों के पास उतनी सम्पदा है जितनी बाकी 99 प्रतिशत के पास है। विश्व के 8 अमीर परिवारों के पास इतनी धन-दौलत है जितनी कि 300 करोड़ लोगों के पास है। हमारे देश की 70 प्रतिशत सम्पत्ति केवल 57 परिवारों के पास ही जमा है। एक तरफ जहाँ मजदूर वर्ग को उनके वैध अधिकारों से वंचित कर बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति का संचय कुछ ही अमीर घरानों के हाथों में हो गया है। इसलिए मुटठीभर लोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। दूसरी तरफ बेरोजगार, भूखे और छंटनीग्रस्त मजदूर भुखमरी और बिना इलाज के मरने पर मजबूर हैं। क्या इस प्रकार की असमानता के रहते समाज को किसी भी प्रकार से समतावादी कहा जा सकता है? पूंजीवाद कभी भी समानता स्थापित नहीं कर सकता है, बल्कि यह असमानता पर आधारित है। लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना तो दूर रहा, उल्टे पूंजीवाद इसे खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। यह आज राष्ट्रवादी- धार्मिक-जातिवादी-नस्ली नफरत और झगड़े-फसादों के साथ-साथ युद्धोन्माद भड़काकर लोगों के आपसी भाईचारे को खत्म कर रहा है। आज पूंजीवाद में स्वतंत्रता का अर्थ है बेरोकटोक लूट व शोषण करने की स्वतंत्रता–एकाधिकारी पूंजीपतियों के लिए लूट-खसोट और शोषण-दमन का बेलगाम अधिकार। जनता को भूख से, बिना देखभाल और बिना इलाज के मरने और आत्महत्या करने की स्वतंत्रता है। यहाँ विरोध करने का भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुरंत निरंकुश और शोषणकारी व्यवस्था इसे बर्बरता से कुचल देती है।

बुर्जुआ जनवाद का अध:पतन

लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सत्ता के बजाय यह अब पूंजी की ताकत के लिए, पूंजी की ताकत के द्वारा और पूंजी की ताकत की सत्ता है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद एक के बाद एक बहुत से राज्यों में चुनाव होंगे। इन चुनावों का परिणाम कौन तय करता है? क्या जनादेश चुनाव परिणामों के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है? ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है लेकिन वास्तविकता में यह सत्तासीन बुर्जुआ वर्ग ही है जो चुनाव परिणामों को तय करता है। सिर्फ एकाधिकारी पूंजीपति ही तय करते हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा। अथाह मात्रा में काला और सफेद धन चुनावों में खर्च किया जाता है। अपनी चुनावी संभावनाओं को चमकाने के लिए राजनैतिक पार्टियाँ एकाधिकारी पूंजीपतियों द्वारा दिए गए धन का इस्तेमाल करती हैं और एकाधिकारी पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित मीडिया एक विशेष पार्टी या गठबंधन के समर्थन में लहर बनाने का काम करता है और सत्तासीन बुर्जुआ वर्ग के निर्देश पर ही नौकरशाही भी काम करती है। राजनैतिक रूप से अचेत तथा असंगठित जनता भ्रमित और गुमराह हो जाती है। धनबल-बाहुबल-मीडिया बल और प्रशासकीय ताकत के द्वारा चुनावों में धांधली की जाती है। वोट एक खरीद-फरोख्त की वस्तु में तब्दील हो जाती है। लाखों-लाख बेरोजगार युवकों को चुनाव के समय में काम करने के लिए खरीद लिया जाता है। यही आज बुर्जुआ लोकतंत्र का असली चेहरा है। अमेरिका समेत सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में इसी प्रक्रिया से लोकतांत्रिक चुनाव सम्पन्न होते हैं। भारत समेत सभी देशों के बुर्जुआ राजनीतिज्ञ मौकापरस्त, झूठे और धोखेबाज हैं। वे केवल जनता को धोखा देते हैं। वायदों को तोड़ने के लिए वायदे करते हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर प्रकार की तिकड़मों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब चुनाव एक धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। बुर्जुआ वर्ग चुनावों के नाम पर लोगों को झांसा दे रहा है।

जब पश्चिम में बुर्जुआ लोकतंत्र अस्त हो रहा था और पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब रहा था तब पूर्व में सर्वहारा जनवाद के उदय ने दुनिया की प्रख्यात हस्तियों को बहुत ही आकर्षित किया था। उन्होंने रूसी सर्वहाराओं द्वारा असल बराबरी, भाईचारे और स्वतंत्रता के बैनर बुलंद किये जाने का तहेदिल से स्वागत किया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1930 में कहा था कि "अगर मैं रूस न आता तो मेरे जीवन की तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाती...। यहाँ पर हो रहे असाधारण काम ने मुझे सबसे अधिक अचम्भित किया है... मैं देख सकता हूँ कि ये नई दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" (रूस से चिटठी) बाद में 1939 में उन्होंने अमिया चक्रवर्ती को लिखा कि इस तपोवन समाजवादी रूस में मैं मानवजाति का एक नया युग शुरू होते देख रहा हूँ।...इसलिए मैं खुशी और उम्मीद से भर गया हूँ ... मानवजाति के इतिहास में इस तरह के आनंद और उम्मीद का स्थाई कारण मैंने और कहीं नहीं देखा है। मैं इनकी दीर्घ विजय की कामना करता हूँ। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा कि "19वीं शताब्दी में जर्मनी ने मार्क्सवादी दर्शन के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और 20वीं शताब्दी में रूस ने सर्वहारा क्रांति, सर्वहारा सरकार और सर्वहारा संस्कृति के माध्यम से विश्व सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध किया है।" (1933 में लंदन में दिये गए भाषण से) "मौजूदा विश्व व्यवस्था में असंख्य धाराओं और प्रतिधाराओं को दो मुख्य ताकतों के रूप में बांटा जा सकता है–एक साम्राज्यवादी ताकतें और इनकी प्रतिधारा के रूप में आगे बढ़ रही साम्यवाद की ताकतें। इसलिए हिटलर की हार का अर्थ है साम्यवाद की स्थापना।" (क्रोस रोड्स) उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने नवम्बर क्रांति द्वारा स्थापित सोवियत समाजवाद की अभूतपूर्व प्रगति को देखकर ऐसा कहा था।

यूएसएसआर में किया गया समाजवादी संविधान को स्वीकृत

हमारे देश के संविधान का निर्माण किसने किया? साम्राज्यवादी देशों अमेरिका और इंग्लैण्ड का संविधान किसने निर्मित किया? इसे कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने निर्मित किया जो बुर्जुआ विचार से प्रभावित थे। संविधान राज्य के ढांचे को निश्चित करता है। संविधान बताता है कि सरकार और प्रशासन कैसे काम करेगें, नए कानूनों को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

उ.प्र. में बिजली दर बढ़ोत्तरी का विरोध

उ.प्र. की भाजपा-नीत योगी सरकार ने स्थानीय निकाय का चुनाव जीतते ही बिजली की दर में 100 से 150 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इस मूल्यवृद्धि से बड़े उद्योगों को बाहर रखा गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.80 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि यह सरकार पूंजीपति-परस्त और जनविरोधी है। सरकार द्वारा बकाया राशि की भरपाई करने के बजाय बिजली दर में वृद्धि करना कभी भी न्यायोचित कदम नहीं हो सकता जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दामों में 40 प्रतिशत की कमी तथा जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत होने से बिजली उत्पादन खर्च में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आ गयी है।

बिजली दर वृद्धि के सरकार के इस जनविरोधी कदम के खिलाफ प्रदेश की वामपंथी पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से 20 दिसम्बर को प्रदेशव्यापी विरोध का आह्वान किया गया। मुरादाबाद, कानपुर, जेपीनगर सहित लगभग सभी जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इस दिन मुरादाबाद में वामदलों द्वारा संयुक्त जुलूस निकाला गया जो रेलवे स्टेशन से बुद्ध बाजार, टाउन हाल, कोतवाली गंज होता हुआ कचहरी पहुंचा। महामहिम राज्यपाल, उ.प्र. के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसयूसीआई(सी) की अमरोहा इकाई की ओर से एसडीएम, अमरोहा कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया और जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बिजली दर बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई। वामपंथी नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर आर्थिक बोझ डाल कर सरासर अन्याय किया है।

भवन निर्माण मजदूरों का श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन

नई दिल्ली में श्रम कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए निर्माण श्रमिक

नई दिल्ली : 20 दिसम्बर को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध कर्मकार एकता केन्द्र यूनियन व भवन निर्माण यूनियन के सैकड़ों मजदूरों ने नीमड़ी कॉलोनी स्थित श्रम उपायुक्त के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी माँगों को लेकर नारे लगाए। एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव एम. चौरसिया ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्रम विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। निर्माण मजदूरों को जो कानूनन सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वे नहीं दी जा रही हैं। एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय सचिवमण्डल के सदस्य कॉ. आर.के. शर्मा ने कहा कि श्रम दफ्तर यदि मजदूर के हक सुरक्षित नहीं कर सकता है तो फिर श्रम विभाग किसके लिए है।

एआईयूटीयूसी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश त्यागी ने काकोरी के शहीदों के 90वें बलिदान दिवस को याद दिलाते हुए शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद अशफाक उल्ला खां की साझी शहादत और साझी विरासत को रखा और कहा कि दोनों अलग-अलग धर्म को मानते थे लेकिन वह यह भी मानते थे कि धर्म एक निजी मामला है उसे राजनीति से अलग रखना है। इसलिए वे साथ मिल कर अंग्रेजों से लड़े। साथ साथ ही 19 दिसम्बर को शहीद हुए। ऐसे समय में जब धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, अपने इन महान शहीदों को याद करना बहुत जरूरी है। इस मौके पर श्रम उपायुक्त को भवन निर्माण मजदूरों की यूनियन के महासचिव निर्मल कुमार, कर्मकार एकता केन्द्र के नेता राकेश कुमार के साथ सुरेश कुमार, प्रेमपाल व कन्हैया लाल के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 सूत्री मांगपत्र दिया। इसमें मांग की गई कि न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, वेतन स्लिप, हाजरी कार्ड, छुट्टी, ई.एस.आई., पीएफ आदि से सम्बंधित सभी कानून सख्ती से लागू किये जायें, भवन निर्माण मजदूरों के लंबित दावों का निपटारा शीघ्र किया जाए और उनके कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व समयबद्ध किया जाये, श्रम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म किया जाये आदि। श्रम उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि वे इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु उनसे जो बन सकेगा, वह करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने तय किया है कि वे अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। जोशपूर्ण माहौल में प्रदर्शन का समापन हुआ।

सोनीपत : 21 दिसम्बर को भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा की ने निर्माण मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए श्रम विभाग के कार्यालय पर धरना दिया और अधिकारी को हरियाणा के श्रममन्त्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

श्रमिकों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित

भिवानी (हरियाणा) : 23 दिसम्बर को स्थानीय राजपूत धर्मशाला में 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में और 30 जनवरी के 'जेल भरो' आन्दोलन की तैयारी में श्रमिकों का संयुक्त सम्मेलन किया गया। इसके संचालन के लिए अध्यक्ष मण्डल में एआईयूटीयूसी की ओर से कॉ. रामफल, इन्टक से रामोतार खोरड़ा, एटक से ईश्वर सिंह, एचएमएस से सुरजभान बराड़, सीटू से कमलेश, एसकेएस से यादवीरेन्द्र शर्मा और सर्व कर्मचारी महासंघ से बल्लू बामला रहे। एआईयूटीयूसी की ओर से वक्ता कॉमरेड धर्मवीर सिंह, इन्टक से धर्मवीर लोहान, एटक से बलदेव घणघस, एचएमएस से रतन लोहिया, सीटू से वक्ता ओमप्रकाश रहे, एसकेएस से वक्ता सुखदेव और सर्व कर्मचारी महासंघ से सूरजमल लेघां रहे।

वक्ताओं ने बताया कि केन्द्र व राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकारें रोजगार देने की बजाय, रोजगार छीन रही हैं, मजदूरी बढ़ाने की बजाय महंगाई बढ़ा रही हैं, कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय कच्चा कर रही हैं और तमाम सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों लागू करने की बजाय इनसे कटौती कर रही हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के शासनकाल से ही घोर जनविरोधी विनाशकारी उदारीकरण, निजीकरण की नीति 1991 में लागू की गई थी। बीजेपी उसी की निरन्तरता में इसे और भी तेजी से लागू कर रही है। दोनों के ही शासनकाल में इन मांगों को लेकर देशव्यापी हड़तालें हुई लेकिन कांग्रेस की तरह ही बीजेपी सरकार भी कारपोरेट घरानों के वर्ग स्वार्थ में मजदूर-कर्मचारियों की इन जायज मांगों की न केवल अनदेखी कर रही है, बल्कि उससे भी तेज हमले कर रही है। इसलिए देशव्यापी जोरदार आन्दोलन गठित करने की जरूरत है। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था घोर संकटग्रस्त है। सालों साल से शोषण करते आ रहे धनकुबेर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के संकट का सारा बोझ मजदूर-किसानों पर डाल देने पर तुली हुई है। पूंजीपति वर्ग का कहना है कि उनको चीजों के दाम बढ़ाने, मजदूरों की छंटनी करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। सरकार का जन कल्याण और जन सेवा से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसी का नाम उन्होंने 'सुधार' रखा हुआ है। इन मजदूर-विरोधी नीतियों से मजदूर-कर्मचारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। तभी से श्रमिकों का संघर्ष जारी है।

श्रमिकों का यह सम्मेलन श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर हो रही मजदूरों के अधिकारों में कटौती बंद करवाने, बढ़ती हुई महंगाई-बेरोजगारी के खिलाफ, मूल्य सूचकांक से जोड़ कर 18000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन करवाने के लिए, सभी को कम से कम 3000 रुपये मासिक पेन्शन दिलवाने के लिए, स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाने के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाये जाने के लिए, स्थायी कामों में ठेका प्रथा बंद करवाने के लिए, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करवाने के लिए, सरकारी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का विनिवेशीकरण बंद करवाने, बोनस, ईएसआई, पीएफ कानून में सभी सीलिंग समाप्त करवाने, आवेदन के 45 दिन के अन्दर यूनियन पंजीकृत की जाने व आईएलओ कन्वेन्शन नं-87 और 98 का भारत सरकार से अनुमोदन करवाने, आदि मांगों को लेकर 30 जनवरी को देशव्यापी 'जेल-भरो' आन्दोलन की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी में 10 जनवरी तक भिवानी के सभी ब्लॉकों में श्रमिक सम्मेलन किये जायेंगे।

श्रमिक नेताओं ने केन्द्रीय श्रम संगठनों की 12 सूत्रीय मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए 30 जनवरी का देशव्यापी जेल भरो आन्दोलन सफल बनाने के लिए मजदूर-कर्मचारियों का आह्वान किया।

भिवानी में श्रमिकों के संयुक्त सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. धर्मवीर सिंह

आशा वर्करों ने किये रोष प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में आशा, उषा के शोषण के खिलाफ 15 दिसम्बर को विरोध दिवस पर आशा उषा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा, उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किये। आशा उषा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, उनका मासिक वेतन सुनिश्चित करो, आशा, उषा को पेन्शन, ग्रेच्यूटी और मातृत्व सुविधाएं आदि सामाजिक सुरक्षा दो, यात्रा भत्ता दो, आदि मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, गुना, देवास आदि विभिन्न जिलों में प्रदर्शन यि गए और कलैक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिये गये।

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 2 का शेष)

कैसे लागू किया जाएगा और कैसे पुराने कानूनों को बदला जाएगा या समाप्त किया जाएगा। संविधान का आधार करके ही लोगों के अधिकारों की घोषणा की जाती है। रूस में क्रांति के बाद एक अस्थाई संविधान को लागू किया गया था। बाद में फिर 1936 में स्थाई संविधान अंगीकर किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि संविधान का मसौदा सबसे पहले लाखों मजदूर-किसानों के बीच वितरित किया गया, जिन्होंने मसौदे को सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए हजारों बैठकें की, मसौदे को पढ़ा, विचारों का आदान-प्रदान किया और अपना मत दिया। उन मतों को आधार करके ही अंततः संविधान बनाया गया। 'लोगों के द्वारा', 'लोगों का' 'लोगों के लिए' का वास्तविक अर्थ यही होता है। ये मजदूर-किसान ही थे जिन्हें सोवियत यूनियन के चुनावों में उम्मीवार के रूप में मनोनीत किया गया था। कौन लोग हैं जो हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं? बहुसंख्या में होने के बावजूद भी गरीब लोग चुनाव लड़ने के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। बुर्जुआ पार्टियों के मनोनीत सदस्य या इन पार्टियों के कुछ समर्थक ही अपने पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं और ये पार्टियां गरीब तबके में से भी कुछ कठपुतली तैयार करती है जिन्हें नामांकित किया जाता है। सोवियत संविधान में किसानों और मजदूरों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त था। वे ही चुनते थे और चुने जाते थे। कहीं और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि 'लोगों के द्वारा', 'लोगों का', 'लोगों के लिए' का असल में यही अर्थ है।

15 सोवियत गणराज्यों ने स्वेच्छा से एकजुट होकर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का निर्माण किया था। सोवियत संविधान में सभी राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। सभी राष्ट्रीयताओं को यह अधिकार भी प्रदान किया गया था कि अगर वे चाहें तो सोवियत संघ से अलग होकर अपने अलग राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। हर एक राष्ट्रीयता को अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार सोवियत संविधान के व्यापक ढांचे के अंर्तगत अपने संविधान का निर्माण करने का अधिकार भी प्राप्त था। यह अधिकार बहुराष्ट्रीयताओं वाले किसी भी बुर्जुआ राष्ट्र में प्रदान नहीं किया जाता है। केवल सोवियत समाजवादी राज्य ने यह अधिकार प्रदान किया था। जो लोग रूस में लोगों के मत से चुनावों में विजयी होते थे, उन्हें अपने कार्यों का नियमित ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ता था और यह अनिवार्य था। किसी भी साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश में यह व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में, जनता चुनावों के बाद अगले पाँच साल तक अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ल तक नहीं देख पाती हैं। अगर सोवियत लोग यह महसूस करते हैं कि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों के पास उन्हें वापस बुलाने का भी अधिकार होता था। किसी भी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देश में लोगों को यह अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इसलिए असल लोकतंत्र की स्थापना सोवियत यूनियन में ही हुई थी।

भारतीय जनता की बढ़ती हुई दुर्दशा व गरीबी

आज दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। हमारे देश की स्थिति से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लोग बदहवास होकर नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं ताकि किसी प्रकार से जीवन यापन कर सकें। बहुत कम को ही नौकरी मिल पा रही है। ये नौकरियाँ भी स्थायी और निश्चित वेतन वाली नहीं हैं। ये सभी ठेके की नौकरियाँ हैं और श्रमिकों को अत्यधिक कम वेतन मिलता है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिलता, कभी कभार तो आधा अधूरा वेतन ही प्राप्त होता है। मजदूरों को वही वेतन स्वीकार करना पड़ता है जो कुछ पूंजीपति मालिक मनमाफिक निश्चित करके उन्हें दे देता है। मालिक द्वारा मजदूरों को किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है। बेरोजगार और गरीब ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह हमारे देश की ही विशेषता नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मयंमार और दूसरे बुर्जुआ देशों में भी यही हालत है। यहाँ तक कि साम्राज्यवादी देशों में सबसे अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका भी बराबर बेरोजगारी की चपेट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया है कि हमारे देश में रोजगारों की किल्लत है। उन्होंने अमेरिकी एकाधिकारी पूंजीपतियों को बताया कि क्योंकि वे दूसरे-दूसरे देशों से सस्ते श्रमिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका के युवक-युवतियाँ बेरोजगारी की समस्या को झेल रहे हैं जिसकी कभी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अमेरिकी पूंजीवाद के हित में अमेरिकी राष्ट्रपति बहुर्राष्ट्रीय निगमों को आदेश दे रहे हैं कि उन्हें नौकरियों की आउटसोर्स करने तथा गैर-अमेरिकियों को नौकरियाँ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अमेरिकी मजदूरों को ही नौकरियों पर रखा जाएगा। इतनी भयंकर बेरोजगारी की समस्या अमेरिका में बनी हुई है। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो एक समय में वैश्वीकरण के प्रमुख पैरोकार था, अब स्वयं ही मझधार में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि वैश्वीकरण की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। अब पूंजीवादी चीन उनका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। अमेरिकी राष्ट्रपति शिकायत कर रहे हैं कि उनके देश का आर्थिक शोषण हो रहा है। चीन और अन्य देश उनके घरेलू बाजार पर धावा बोल रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि उनके देश की सम्प्रभुता को खतरा है। यह कह कौन रहा है? यह स्वयं अमेरिकी साम्राज्यवादियों के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो स्वयं दूसरे देशों की सम्प्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिकी बाजार चीनी उपभोक्ता सामानों से अंटे पड़े हैं और अमेरिकी उद्योगों के शटर बंद हो रहे हैं। अमेरिकी श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए अमेरिकी साम्राज्यवादी 'अमेरिका पहले' का नारा उठा रहे हैं और वैश्वीकरण की संधियों और समझौतों की अवज्ञा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादी चीन के राष्ट्रपति अधिक से अधिक बाजारों को हड़पने के लिए वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे हैं।

सोवियत समाजवाद ने कर दिया था जीवन की सभी आधारभूत समस्याओं का समाधान

1917 में रूसी क्रांति सम्पन्न हुई। प्रथम विश्वयुद्ध में तहस-नहस हुए देश को दोबारा से खड़ा करने में 10 साल लग गए। 1930 में सोवियत संघ ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी को रोजगार मिलेगा। सोवियत संविधान के अनुसार सभी को काम का अधिकार प्रदान किया गया। यह उद्घोषित किया गया कि एक व्यक्ति जब तक काम नहीं करेगा, उसे खाना खाने का अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में कोई भी काम किए बिना नहीं रह पाएगा। वहाँ बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई थी। सोवियत समाजवाद में 70 वर्षों के दौरान न तो बेरोजगारी की समस्या थी, न कोई आर्थिक मंदी हुई, न ही कीमतों में उछाल आया और न ही बाजार में उतार-चढ़ाव आया। सभी जानते हैं कि क्रांति के तुरंत बाद ही लेनिन ने लीग ऑफ नेशन्स में पूर्ण निशस्त्रीकरण का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि हथियारों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए, हमेशा के लिए युद्धों को समाप्त कर दें। लेकिन साम्राज्यवादी-पूंजीवादियों ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। यही आह्वान महान स्टालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद किया था। उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों समेत सभी हथियारों को नष्ट करने की अपील की थी। युद्ध समाज को अत्यधिक खतरा पहुंचता है। लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिएं। क्या किसी दूसरे राष्ट्र ने इस प्रकार का आह्वान किया है? केवल सोवियत संघ ने ही ऐसा किया। क्योंकि समाजवाद में आर्थिक विकास के लिए दूसरे के बाजारों को हड़पने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए समाजवाद में युद्धों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सोवियत संघ ने हमेशा ही वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किए। लेकिन साम्राज्यवादी-पूंजीपतियों ने शांति स्थापित करने के इस आह्वान का कभी भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे क्योंकि साम्राज्यवाद को युद्धों की जरूरत होती है। नृशंस पूंजीवादी शोषण-दोहन के कारण जब एक देश के लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तब साम्राज्यवादी देशों के घरेलू बाजार सिकुड़ जाते हैं। ऐसे समय में एकाधिकारी पूंजीपतियों को विदेशी बाजार हड़पने की जरूरत पड़ती है और विदेशी बाजार को हड़पने और विदेशी बाजार को लूटने-खसोटने में कोई अड़चन आती है तो ये युद्ध शुरू कर देते हैं। पहला और दूसरा विश्वयुद्ध साम्राज्यवादियों की बाजार हड़पने की होड़ की वजह से ही हुए थे। आज भी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें युद्धों की जरूरत है।

भारतीय पूंजीवाद ने भी हासिल कर लिया है साम्राज्यवादी चरित्र

इस संबंध में मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। हरेक साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देश में बेरोजगारी और रोजगारहीनता की समस्या ने लोगों के जीवन को तबाह कर डाला है। बहुत सारे लोग भुखमरी और चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण मर रहे हैं। लेकिन सैन्य बजट लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक सैन्य संधि की है। पहले भी दोनों के बीच सैन्य समझौते व संधियाँ हुई हैं। अब अमेरिकी वाइट हाऊस ने घोषणा की है कि दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अब दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियाँ बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, दोनों देशों के शासक एकाधिकारी स्वयं को दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में मानते हैं इसलिए उन्हें विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। भारतीय पूंजीवाद ने एकाधिकारी पूंजी और वित्तीय पूंजी को जन्म दे दिया है। भारत भी अब एक साम्राज्यवादी शक्ति है। यह दूसरे पड़ौसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यहाँ तक कि इंग्लैण्ड और अमेरिका में भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं। विलम्ब से ही सही, पर मीडिया में आया कि भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों ने अमेरिका में जो उद्योग लगाए हैं, उन उद्योगों की बदौलत 1,12000 अमेरिकियों को रोजगार मिला हुआ है। भारतीय वित्तीय पूंजी यूरोप, अमेरिका, एशिया और मध्यपूर्व में क्रियाशील है। यह भारतीय राष्ट्रीय पूंजी के साम्राज्यवादी चरित्र को दर्शा रहा है। जबकि भारत साम्राज्यवादी चरित्र हासिल कर चुका है, उसके बावजूद भी सीपीआई(एम) और सीपीआई भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ को प्रगतिशील मानते हैं और जन गणतांत्रिक क्रांति की रट लगा रहे हैं।

हालांकि क्रांति-पूर्व रूस में कृषि में सामंती प्रभाव काफी ज्यादा था और पूंजीवाद अत्यधिक कमजोर था लेकिन लेनिन ने कहा था कि क्योंकि 1917 की फरवरी क्रांति के बाद रूसी बुर्जुआ सत्ता पर आसीन हो चुका है, इसलिए रूस में क्रांति का स्तर पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति का है। तदनुरूप उन्होंने समाजवादी क्रांति का नारा दिया और उसे साकार किया। सीपीआई(एम)-सीपीआई ने अपने गैर-मार्क्सवादी और क्रांति-विरोधी सिद्धांत के कारण कभी तो निरंकुश शासन की खिलाफत करने के नाम पर जन संघ से और बाद में बीजेपी से तथा कभी साम्प्रदायिकता का विरोध करने के नाम पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कृपया इस बात को जरूर अपने जेहन में रखें कि भारतीय एकाधिकारी पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ समझौता कर रहे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद चीन का विरोध करने के लिए भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आर्थिक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। लेनिन ने दिखाया था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद से ही पैदा हुआ है और साम्राज्यवाद युद्धों को जन्म देता है। यह युद्धोन्मुखी अर्थव्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों की खरीदने की क्षमता में कमी आने के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं का बाजार सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए साम्राज्यवादियों को हथियार बेचने के लिए एक वैकल्पिक बाजार की जरूरत है। अमेरिका भारत, जापान और दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कृत्रिम प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है। इसी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टालिन ने अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण का नाम दिया था। हमारे देश का शासक एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग भी इसी प्रकार का काम कर रहा है। इसका मायना है लोगों के हितों को ताक पर रखकर वह अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण का सहारा ले रहा है। पूंजीवाद का यह संकट अपरिहार्य है।

सोवियत समाजवाद की कुछ चारित्रिक विशेषताएं

इस दमनकारी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध ही समाजवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियम है लाभ कमाना, अत्यधिक

(शेष पृष्ठ 6 पर)

काकोरी के शहीदों को किया याद

दुर्ग (छत्तीस गढ़) : 21 दिसम्बर को आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारियों अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी व ठाकुर रोशन सिंह के शहादत दिवस पर उनकी याद में स्थानीय बैगा पारा शीतला मंदिर चौक पर सभा की गई। सभा की शुरूआत में चारों क्रांतिकारियों के फोटो पर ए.आई.डी.वाई.ओ. व ए.आई.डी.एस.ओ. के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर और मोमबती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को एआईडीवाईओ व एआईडीएसओ कार्यकताओं ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने तमाम सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए युवाओं को अपने नैतिक व सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करने, वैज्ञानिक सोच अपनाने, समाज के विकास का सही वैज्ञानिक अध्ययन कर अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझने और अपनी असली समस्या के खिलाफ संगठित होकर जोरदार युवा आंदोलन गठित करने की अपील की। 'अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी व ठाकुर रोशन सिंह जिन्दाबाद', 'क्रांतिकारियों को इतिहास में उचित स्थान दो', 'क्रांतिकारियों के जन्म दिवस व शहादत दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करो', 'अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी व ठाकुर रोशन सिंह हम तुम्हें भूले नहीं, भूलेंगे नहीं', 'जनजीवन की समस्याओं के खिलाफ युवा आंदोलन तेज करें', 'सांप्रदायिकता पर रोक लगाओ', 'युवाओं को नशे में डूबाना बन्द करो', 'अपसंस्कृति-अश्लीलता पर रोक लगाओ' आदि नारों के साथ सभा का समापन हुआ।

जयपुर (राजस्थान) : शहीदों की याद को तरोताजा करते हुए ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से यहां जुलूस निकाला गया और सभा कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दरभंगा (बिहार) : 19 दिसम्बर को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (ऑल इण्डिया डीएसओ) दरभंगा के तत्वावधान में काकोरी घटना के महान शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी, ठाकुर रौशन सिंह का शहादत दिवस स्नातकोत्तर इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मनाया गया। मुजफ्फरपुर में भी सभा कर शहीदों को याद किया गया।

हरियाणा : 19 दिसम्बर को ऑल इण्डिया डीएसओ व ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से सोनीपत में छोटूराम धर्मशाला में सभा की गई। सभा को एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता ऑल इण्डिया डीवाईओ के जिला प्रधान कॉ. देवेन्द्र सिंह ने की और संचालन ऑल इण्डिया डीएसओ के कॉ. राजेश ने किया। 18 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में एसयूसीआई(सी) द्वारा काकोरी कांड के शहीद महान क्रन्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेन्द्र लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह का शहादत दिवस पर मशाल जुलूस निकाला गया। मण्डी अटेली में ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से काकोरी के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए राधा कृष्ण धर्मशाला में हुई स्मृति सभा की अध्यक्षता जिला संयोजक सतीश कुमार ने की।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉमरेड बलबीर सिंह का निधन

रोहतक (हरियाणा) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की रोहतक जिला कमेटी के सदस्य और एआईयूटीयूसी के सक्रिय कार्यकर्ता कॉमरेड बलबीर सिंह की दुखद मृत्यु पर 31 दिसंबर को पार्टी की रोहतक जिला कमेटी के सचिव कॉमरेड अनूप सिंह ने गहरा शोक प्रकट किया और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 30 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। वे 59 वर्ष के थे।

विदित रहे कि कॉमरेड बलबीर सिंह रोहतक स्थित नवभारत फैक्ट्री में स्थायी कर्मचारी थे। वे एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की रोहतक जिला कमेटी के सदस्य थे। वे लम्बे अर्से से ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे 2013 में बंगलौर में हुए एआईयूटीयूसी के 20वें अखिल भारतीय सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। वे लगभगभग 25 साल पहले पार्टी के सम्पर्क में आये थे और कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से प्रभावित होकर निरंतर पार्टी द्वारा विभिन्न जन आंदोलन व मजदूर आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहे। वे बड़े ही निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ता थे। 7 नवम्बर को महान नवंबर क्रान्ति के शताब्दी के उपलक्ष्य में रोहतक तथा 17 नवम्बर को कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय समापन समारोह में भी बड़े उत्साह व जोश के साथ शामिल हुए थे।

पार्टी में उनकी कमी हमेशा रहेगी। उनके सम्मान में पार्टी कार्यालय पर आधा झंडा झुकाया गया व कार्यालय में उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। कॉमरेड बलबीर लाल सलाम!

सागर में हुए दुष्कर्म के खिलाफ रोष प्रदर्शन

सागर में हुए दुष्कर्म के खिलाफ और मध्यप्रदेश में बढ़ रहे लगातार महिलाओं और बच्चियों पर अपराध व नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ए.आई.डी.एस.ओ., ए.आई.एम.एस.एस. और ए.आई.डी.वाई.ओ. की ओर से 16 दिसम्बर को सागर, भोपाल, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर आदि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोष प्रदर्शन किए गए। ऑल इण्डिया महिला सास्कृतिक संगठन की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती जॉली सरकार व प्रदेश सचिव श्रीमती रचना अग्रवाल ने दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने की माँग की ताकि दुष्कर्मियों में कानून का डर पैदा हो सके। जगह-जगह नुक्कड़ सभा, रेली, केंडल मार्च, श्रद्धांजली सभा व विचारों की प्रदर्शनी और नुक्कड़ सभा की गई।

सागर

यूरिया खाद मुहैया कराने की किसानों ने की मांग

तोशाम (हरियाणा) : 21 दिसम्बर को यूरिया खाद समय पर मुहैया कराने की मांग पर ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को एसडीएम तोशाम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल में संगठन के जिला सचिव कॉ. रोहताश सैनी, जिलाध्यक्ष कॉ. जिले सिंह और जिला कमेटी सदस्य कॉ. सुखबीर सिंह ढाणी माहू, राजकुमार रिवासा, अनिल दुल्हेड़ी, तेलूराम खरकड़ी सौहान, नरसिंह बागनवाला, ओमप्रकाश भुरटाना आदि शामिल थे। ज्ञापन में मांग की गई कि यूरिया खाद का पूरा प्रबन्ध किया जाये, यूरिया खाद को जीएसटी से बाहर किया जाए और यूरिया के रेट कम किये जायें।

किसान नेता रोहताश सिंह सैनी ने कहा कि यूरिया खाद समय पर मुहैया न होने की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। अधिकतर किसान जब यूरिया लेने जाते हैं तो आधार कार्ड एवं अंगूठा निशान के मिलान न होने से परेशान हैं। यूरिया खाद पर जीएसटी लगाने का फैसला एकदम किसान-विरोधी है। इससे यह बेहद महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ आन्दोलन करने के सिवा और कोई बचने का रास्ता नहीं है।

तोशाम : मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता कॉ रोहताश व अन्य

शहीद ऊधम सिंह को दी श्रद्धांजलि

कुरूक्षेत्र (हरियाणा) : भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाण व ऑल इण्डिया डीवाईओ द्वारा सन्निहित पार्क में ऊधम सिंह जयन्ती धूमधाम के साथ मनाई गयी। ऊधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। डीवाईओ के प्रदेश सचिव बलवान सिंह मुख्य वक्ता थे। नन्दलाल, नरेश कुमार ने भी सभा में बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर-किसानों, छात्र- नौजवालों, दस्तकारों सहित सभी शोषित-पीड़ित लोगों को उनकी ज्वलंत मांगों को लेकर देशव्यापी ताकतवर आन्दोलन में लाना होगा। यही ऊधम सिंह जैसे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कुरूक्षेत्र

नारनौल : ऑल इण्डिया डीवाईओ की तरफ से शहीद ऊधम सिंह की 118वीं जयन्ती पर 26 दिसम्बर को मशाल जुलूस निकाला गया जो पीडब्लूडी रेस्ट हाऊस से चलकर आजाद चौक पर पहुंचकर स्मृति सभा में बदल गया। सभा का संचालन एआईडीवाईओ की नारनौल इकाई के प्रधान बिजेन्द्र सिंह ने किया। सभा को डीवाईओ के जिला संयोजक कॉ. सतीश ने संबोधित किया।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 4 का शेष)

मुनाफा कमाना, लगातार अत्यधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करना। अत्यधिक मुनाफा बटोरने का अर्थ है मजदूर वर्ग का अत्यधिक शोषण। इसके विपरीत, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है आम जनता की बढ़ती हुई भौतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार उत्पादन में वृद्धि करना। मजदूरों का शोषण करके अत्यधिक मुनाफा कमाने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मजदूर-किसान अधिकाधिक रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समाजवाद में न तो बाजार संकट है, न मंदी की समस्या है, न बेरोजगारी की समस्या है और न ही छंटनी की समस्या है। समाजवाद लगातार प्रगति करता गया और मजबूत होता गया। सोवियत संघ में दो प्रकार के वेतन थे। एक था आर्थिक वेतन और दूसरा था सामाजिक वेतन। फैक्ट्रियों में वेतन, फैक्टरी कमेटी और मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा एक साथ मिलकर तय किया जाता था। वेतन का आधा हिस्सा मजदूर स्वयं रखकर दूसरा हिस्सा समाजवादी सरकार को दान में दे देते थे। सरकार वेतन का एक हिस्सा क्यों और किसलिए लेती थी? यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। मजदूरों के स्वैच्छिक अंशदान से जो पैसा एकत्रित किया जाता था, उसे उत्पादान बढ़ाने के लिए, नए साधनों और तकनीकी को खोजने के लिए, प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लगातार दी जा रही युद्धों की धमकियों को विफल करने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए सैन्य ताकत का विकास करने में लगाया जाता था। सर्वोपरि, सामाजिक जनकल्याण के कार्यक्रम थे। रूसी श्रमिकों को नाममात्र किराये पर घर उपलब्ध कराया जाता था, भोजन तथा दूसरी आवश्यक चीजें बहुत ही कम दामों पर मुहैया करवाई जाती थी। श्रमिकों को बिजली, ईन्धन, पानी और फैक्टरी यूनिफार्म नि:शुल्क मुहैया करवायी जाती थी। रूस में सब को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। प्राथमिक शिक्षा 80 मातृभाषाओं में प्रदान की जाती थी। शुरूआत में 30 भाषाओं की कोई वर्णलिपि नहीं थी, लेकिन भाषाविदों ने वर्णमालाओं को तैयार किया। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क थी। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। क्या आप उस प्रकार की सुविधाओं के बारे में सोच भी सकते हैं? सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, शिक्षा एक पण्य वस्तु में तब्दील हो चुकी है। जिनके पास पैसा है, केवल वे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी रूस में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नि:शुल्क थी। अस्पतालों के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। डॉक्टरों और नर्सों की संख्या लगातार बढ़ाई जाती थी। वहाँ पर बहुत सारी नई दवाओं की भी खोज की गई थी। विश्व में इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं कौन प्रदान कर सकता है? पूरे पूंजीवादी विश्व में स्वास्थ्य सेवा को भी एक खरीद-फरोख्त की वस्तु बना दिया गया है। कितने सारे लोग जरूरी चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। लेकिन सोवियत रूस में सभी नागरिकों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नि:शुल्क मुहैया करवायी जाती थी। हमारे देश में आप असंख्य भिखारी देख सकते हैं। अंधेरा होते ही बहुत सारी अभागी महिलाएं अपना जिस्म बेचकर अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर निकल जाती हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका का भी यही नजारा है। रूस में वेश्यावृत्ति का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया था। जो भी लोग इस दुखदायी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, क्रांति के बाद उनका पुनर्वास करवाया गया था। मैं इस घृणित शब्द वेश्या का उच्चारण तक भी नहीं करना चाहता हूँ। यह एक अपमानजनक शब्द है। जार के समय में रूस में बहुत सारी महिलाएं देह व्यापार में संलिप्त थी। समाजवाद स्थापित होने के बाद उन्हें इस पतित व्यवसाय से निकाला गया, पुनर्स्थापित किया गया और उचित प्रशिक्षण और शिक्षा से लैस करके उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लायक बनाया गया। सभी पूंजीवादी देशों में बहुत सारे भिखारी और आवारा बच्चे सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएंगे। सोवियत संघ में बच्चा या बड़ा कोई भी भिखारी नहीं था। सभी आवारा बच्चों व भिखारियों का पुनर्वास किया गया था। हमारे देश समेत सभी पूंजीवादी देशों में मुख्य रूप से महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद हैं। वे क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश नहीं पाती हैं। उन्हें सही मायने में शिक्षित होने का अवसर ही मिल नहीं पाता है। पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें घर में बंदी बनाकर रखा जाता है। सोवियत समाज ने नारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। महिलाओं और पुरुषों को समान भागीदारी प्रदान की गयी थी। महिलाओं तथा पुरुषों सभी के लिए समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं केवल रसोईघर में, कपड़े धोने में या घरेलू कार्यों में जकड़ी न रहें इसलिए समाजवादी रूस में 10-15 परिवारों को मिलाकर सामूहिक रसोईघरों, सामूहिक भोजनालयों और सामूहिक धोबीघाटों की व्यवस्था की गई थी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 12 हफ्ते पहले और प्रसव के 12 हफ्ते बाद तक पूर्ण वेतन के साथ छुटटी प्रदान की जाती थी। उसके बाद भी पूर्ण वेतन के साथ एक साल का अवकाश प्रदान किया जाता था। उसके बाद जब माँ को काम पर आना पड़ता था, तो बच्चे को क्रेच में छोड़ दिया जाता था। समाजवादी सरकार ने बच्चे के खाने और कपड़े की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। वहाँ पर बच्चों को पालने के लिए किंडरगार्टन और नर्सरियाँ थी। सोवियत समाजवाद में मजदूर-किसानों को साल में एक बार पूर्ण वेतन सहित 15 दिन का अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया जाता था। सभी मजदूर-किसान इन छुटिटयों में आराम के लिए, मनोरंजन और स्वास्थ्य लाभ के लिए समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर बने स्वास्थ्य गृहों में जाते थे। शुरूआती दिनों में श्रमिकों को हफ्ते में 6 दिन और एक दिन में 8 घण्टे की ड्यूटी करनी पड़ती थी। उन बुर्जुगों और विकलांग लोगों की जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी थी जिनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। रूसी समाजवाद में कोर्ट में न्याय पाने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता था। सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। यहाँ तक की वकीलों का खर्च भी। अध्यापकों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और लेखकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता था। उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी स्वयं सरकार की ही थी। वहाँ गांव-शहरों में हजारों की संख्या में पुस्तकालय बनाए गए थे। जहाँ जाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय तथा किसी भी देश की पत्रिका या पुस्तक का अध्ययन कर सकता था। इसी प्रकार से बहुत सारे सिनेमा हाल और थियेटर थे जहाँ पर जाकर व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता था। ये सभी नि:शुल्क थे। वहाँ पर सरकार द्वारा संचालित फ्री खेल प्रशिक्षण विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था की गई थी। इसी के परिणामस्वरूप सोवियत संघ ने ओलंपिक खेलों में भी सबसे उन्नत स्थान हासिल किया था। वहाँ विज्ञान का इतना अधिक विकास हुआ था कि पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित नोबल कमेटी द्वारा 12 सोवियत वैज्ञानिकों को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। मैंने सोवियत संघ की कुछ ही विशेषताओं की यहाँ चर्चा की है जिसे सुनकर किसी को भी ऐसा प्रतीत होगा कि मैं किसी स्वप्नलोक की बातें आपको बता रहा हूँ। लेकिन सोवियत समाजवाद ने महान लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में मार्क्सवाद को सही तरीके से लागू करके इसे वास्तव में ही क्रियान्वित करके दिखाया था। यह किस तरह से संभव हो पाया?

सोवियत क्रांति ने सिद्ध की मार्क्सीय विज्ञान की अचूकता

क्रांति और समाजवाद लेनिन का व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं था। उन्होंने वस्तुगत परिस्थितियों में मार्क्सवाद की शिक्षाओं को लागू किया था। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की भी मात्र एक कल्पना नहीं थी। मार्क्स ने सत्य को ढूंढ़ने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया। मार्क्स से पहले के दार्शनिकों और चिंतकों के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस समय एक दार्शनिक की अनुभूति को ही सत्य मान लिया जाता था। यह मान लेना कहाँ तक सही है कि किसी भी व्यक्ति या विचारक या किसी पुस्तक के लेखक का व्यक्तिपरक चिंतन या निष्कर्ष वस्तुगत सत्य को ही प्रतिबिम्बित करता है? क्या सच को जानने का यह तरीका सही है? फिर कैसे सभी लोग इलैक्ट्रॉन, बिजली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के विषय में एक समान समझदारी हासिल कर पाएंगे? कैसे सभी लोग बादलों के बनने और बारिश होने तथा ज्वार-भाटा आने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे? इन सभी सवालों पर विभिन्न विचारकों ने भिन्न-भिन्न विचार रखे हैं। अलग-अलग पुस्तकों में इन सवालों पर भिन्न-भिन्न उत्तर दिये गये हैं। इसलिए वैज्ञानिक निरीक्षण-परीक्षण और सत्यापित सत्य के आधार पर ही एक समान और सही समझदारी पैदा की जा सकती है। विज्ञान की हर शाखा एक विशेष क्षेत्र या दायरे का अध्ययन करती है और उन विशेष नियमों की खोज करती है जो उस विशेष विज्ञान के क्षेत्र या दायरे को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से गले में पहनने वाली माला विभिन्न रंगों के फूलों से गूंथी होती है, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने प्रत्येक क्षेत्र के विशेष सत्य को द्वंद्वात्मक ढंग से समन्वित, एकीकृत और सहसंबद्धित करके वस्तुजगत को नियंत्रित करने वाले सामान्य और सार्वभौमिक नियम खोजे थे। ये ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सामान्य नियम हैं। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति, जीव जगत, मानव जीवन-सब कुछ परिवर्तनशील है और गतिशील है और यह गति कुछ सामान्य नियमों द्वारा संचालित होती है। जिस प्रकार से प्रकृति जगत में होने वाले परिवर्तनों और वस्तुजगत में होने वाले परिवर्तनों को विज्ञान का प्रयोग करके जाना जा सकता है उसी प्रकार से मानव समाज में होने वाले विकास और परिवर्तनों को भी विज्ञान के नियमों द्वारा समझा जा सकता है।

धर्म के संबंध में मार्क्स के विचार

मैं यह बात और कहना चाहूँगा कि दास प्रभुओं के समाज में मुक्ति का जो विचार आया था वह दासों को मुक्त करने की सामाजिक आवश्यकता की वजह से आया था। शोषित-पीड़ित दास मुक्ति चाह रहे थे। उनके आँसुओं ने ही एक दिन धर्म के विचार को जन्म दिया। यह बात सबसे पहले महान मार्क्स ने बताई थी और बाद में कॉ. शिवदास घोष ने इसे और अधिक विस्तृत रूप से समझाया था। बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि हम मार्क्सवादी हैं इसलिए धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मार्क्सवादी विचारों ने ही सबसे पहले इतिहास के एक विशेष युग में धर्म के द्वारा निभाई गई प्रगतिशील भूमिका को मान्यता दी थी। इसके विपरीत बुर्जुआ विचारकों जैसे बैकन, लॉक, होब्स, स्पीनोजा, ह्युम, कान्ट और फूअरबाक ने धर्म को इतिहास का विपथगमन बताया था। यह सत्य है कि धार्मिक विचार मानव सभ्यता के आदिम काल से मौजूद नहीं थे। अगर आप अण्डमान जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के मूल निवासी 'जरोआ',जो वहाँ पर रहते हैं, उनके पास न तो कोई निजी सम्पत्ति है, न सम्पत्ति के मालिकाने की ही कोई अवधारणा मौजूद है और न ही समाज अमीर और गरीब में बंटा है। इसलिए भगवान जैसी कोई अलौकिक सत्ता की जानकारी भी इन्हें नहीं है। धर्म का उदय दास मालिक युग में ही हुआ था। इसलिए मार्क्स ने बताया था कि ''धर्म शोषित-पीड़ित प्राणियों की आह है, हृदयहीन संसार का हृदय है और आत्माविहीन अवस्था की आत्मा है।(हीगेल का दर्शन के अधिकार की आलोचना) एंगेल्स ने इसाई धर्म के विषय में जो कहा था, वह सभी धर्मों पर लागू होता है। उन्होंने कहा था कि ''ईसाइयत और मजदूरों का समाजवाद, दोनों ही आने वाले समय में दुख और दासता से मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देते हैं। ईसाइयत जीवनोत्तर अर्थात् मृत्यु के बाद स्वर्ग में मुक्ति की बात करता है लेकिन समाजवाद इसी जन्म में समाज परिवर्तन के बाद मुक्ति की बात करता है।('ऑन दि हिस्ट्री ऑफ अरली क्रिश्चनिटी) इसी की आगे व्याख्या करते हुए कॉ. शिवदास घोष ने दिखाया कि भगवान का विचार कहाँ से आया? भगवान का विचार समाज में उस समय आया जब समाज में वर्ग-विभाजन हो गया था, स्थायी सम्पत्ति पैदा हो चुकी थी और शासक वर्ग के तहत एक प्रकार का प्रशासनिक

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 6 का शेष)

ढाँचा गठित हो गया था। सामाजिक विकास की यह अवस्था जिसमें प्रशासन का प्रमुख एक शासक होता है, जो स्वेच्छाचारी कानूनों को लागू करके शासन चलाता है, जिनका सभी को पालन करना पड़ता है। यह समाज कुछ हद तक सुसंगठित और अनुशासित रूप से चलता है, जिसमें व्यक्ति एक विचार के साथ बंधा होता है। वह देखता है कि उसके चारों तरफ का जीवन कुछ कानूनों से संचालित हो रहा है। सूर्य का उदय और अस्त होना, दिन और रात का बनना, सर्दी-गर्मी और फिर बरसात का मौसम आना यह सब एक समय अनुसार परिवर्तित होता है। ज्वार-भाटे और लहरों का आगमन, वैकल्पिक रूप से अमावस्या और पूर्णिमा का आगमन–यह सब एक नियमित क्रम से हो रहा है और निश्चित नियमों का पालन करते हुए हो रहा है इसलिए इन्सान के दिमाग में यह विचार आया कि जिस प्रकार से कानून बनाने वाले शासक के बिना समाज नहीं चल सकता, उसी प्रकार इतना व्यापक ब्रह्माण्ड और समाज दोनों के ही नियम से चलने की समरूपता को देखकर ही इन्सान के दिमाग में सवाल पैदा हुआ और इसी आधार पर सुपर मास्टर या भगवान की अवधारणा ने जन्म लिया। आप सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज विकास की एक विशेष अवस्था में धर्म ने ही नीति-नैतिकता, मूल्यबोधों, सही और गलत तथा किसी को तिरस्कार न करने की धारणा को आगे बढ़ाने में मदद की थी। परिणामस्वरूप अनुशासन की समझ में बढ़ोतरी हुई, जिसने समाज में एकजुटता और समन्वय स्थापित करने में मदद की। इस दृष्टिकोण से भी धर्म ने सामाजिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। (मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ पहलू) उस समय में धर्म प्रचारकों के दिमाग में जिस विचार का जन्म हुआ वह यह था ईश्वर ही सबको पैदा करने वाला है। दास और दासप्रभु, दोनों ही भगवान के बंदे हैं। उस समय सभी समस्याओं का जो समाधान धर्म गुरुओं के दिमाग में ईमानदारी से सबसे पहले सूझा था, वह था धर्म गुरुओं के उपदेश या दैववाणी। धार्मिक उपदेश देने वाले इन धार्मिक गुरुओं को दासप्रभुओं द्वारा सताया जाता था। उनमें से बहुतों को मार भी दिया जाता था तथा कुछ भूखों मर जाते थे। कॉ. शिवदास घोष ने दिखाया कि दास प्रथा के खिलाफ होने वाले संघर्ष में धर्म ने समाज को नीति-नैतिकता का आधार प्रदान किया था तथा सामाजिक बंधन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को फलने-फूलने में मदद दी थी। अर्थात् धर्म ने एक समय में समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही है इतिहास। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि बाद में इतिहास बदलने के क्रम में धर्म की यह प्रगतिशील भूमिका समाप्त हो गई और धर्म अप्रचलित हो गया। उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय की किसी भी समस्या के विषय में चर्चा या समस्या के समाधान की तरफ कोई भी संकेत आज धार्मिक पुस्तकों में नहीं मिलता है। जबकि एक समय में बुर्जुआ वर्ग ने जिस धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वह आज शोषित-पीड़ित लोगों को भ्रमित करने के लिए उसी धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को प्रभावित करने के लिए यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनके सभी दु:ख-तकलीफों का कारण उनके पूर्वजन्म में किए गए कार्य हैं। पूंजीवादी शोषण उसका कारण नहीं है और स्वयं उन्होंने अर्थात् पूंजीपति मालिकों ने और बड़े व्यवसायियों ने पूर्वजन्म में इतने अधिक धार्मिक कार्य और पुण्य किए हैं जिनके बदले में उन्हें बिना किसी भेदभाव के गरीबों को सताने और उनका शोषण करने तथा उनका खून तक चूस लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। जैसे कि यही विधाता का आदेश है और इसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए पूंजीवाद को आज धर्म की आवश्यकता है और साथ ही साथ लोगों में तार्किक और वैज्ञानिक विचारों को खत्म करके उन्हें अपने राजनैतिक एजेंटों के चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनमें धर्मान्धता और कट्टरता का प्रसार करना आज पूंजीवाद के लिए आवश्यक हो गया है। धूर्त शोषणकारी सत्तासीन पूंजीपति वर्ग और उसके सेवकों के लिए यह और कुछ नहीं, बल्कि बहुत ही दुष्टतापूर्ण कार्य है। एक दूसरा तबका धर्म को एक व्यवसाय बनाकर उससे अकूत धन-दौलत कमा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत से साधारण धार्मिक लोगों को अगर सही प्रकार से समझाया जाता है, तो वे शोषण और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष में जरूर हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे धर्म अप्रचलित हो गया है और अपना महत्व खोकर वह प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के हाथों के एक हथियार के रूप में तब्दील हो गया है। मार्क्सवाद ने दिखाया है कि एक समय में दासों की मुक्ति और समाज की भलाई के लिए धर्म का उदय हुआ था। आप यह भी जानते हैं कि धर्म के आधार पर ही सामंती-राजशाही शासन कायम हुआ था। फिर वही धर्म सामंती प्रभुओं और राजतंत्र के हाथों में भूदासों पर दमन-उत्पीड़न का एक हथियार बन गया। सामंती शोषण से मुक्ति की सामाजिक आवश्यकता से ही उस समय विकसित हुए जनवादी और वैज्ञानिक विचारों, जो धर्मांधता का विरोध करते थे के आधार पर ही बुर्जुआ जनवादी क्रांति को लाया गया था। उस समय बुर्जुआ वर्ग ने समानता-स्वतंत्रता और भाईचारे के नारे को बुलंद किया था जिसे वे आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। मार्क्स ने ही सबसे पहले दिखाया कि बुर्जुआ वर्ग क्यों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा कायम नहीं कर पाया। उन्होंने व्याख्या करके दिखाया है कि किस प्रकार मजदूरों को उनके जायज हकों से महरूम करके पूंजीवाद अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। इससे पहले कोई भी बुर्जुआ अर्थशास्त्री इसे दर्शा नहीं पाया था। इसलिए, शोषित-उत्पीड़ित दासों के आँसुओं और आहों में प्रकट होने वाली उनकी मुक्ति की चाह निरंतरता के साथ जारी रहते हुए, न तो सामंतवाद में और न ही पूंजीवाद में पूर्ण हो सकी। उनकी उस चाह ने मार्क्सवाद के रूप में मूर्त रूप लिया। विज्ञान को आधार बनाकर मार्क्स ने बताया कि वान्छित और अभिलक्षित मुक्ति संभव है। उन्होंने व्याख्या करके दिखाया कि प्रकृति जगत और वस्तु जगत की तरह ही मानव समाज भी परिवर्तनशील है। आदिम साम्यवादी समाज से दास समाज का आना और वहाँ से सामंतवाद और फिर पूंजीवाद में परिवर्तन होना न तो कोई अचानक से घटने वाली घटना थी और न ही यह किसी की इच्छा या कपोल कल्पना पर आधारित था। यह कुछ निश्चित नियमों से संचालित होता आया है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि जब से समाज में वर्ग-विभाजन आया, तभी से वर्ग-संघर्ष ने सामाजिक परिवर्तन के लिए संचालिका शक्ति के रूप में काम किया है। इसी तरह वर्ग-संघर्ष के माध्यम से ही दासों ने दास व्यवस्था को खत्म किया और फिर भूदासों ने उभरते हुए बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में सामंती राजशाही को उखाड़ फेंका था। इसी तरह मजदूर भी वर्ग-संघर्ष को और भी तेज करके पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंकेगा और समाजवाद कायम करेगा। उसके बाद फिर साम्यवाद की स्थापना होगी और इसी क्रम में एक और उन्नत समाज का निर्माण होगा। यह ऐतिहासिक तौर पर निश्चित वैज्ञानिक नियम है। इसमें महान मार्क्स द्वारा प्रदान किए गए वैज्ञानिक समाजवाद के दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

(शेष अगले अंक में)

कक्षा-1 से पास-फेल चालू करने

(पृष्ठ 1 का शेष)

एआईडीएसओ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भास्करानन्द के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। इसमें उड़ीसा से शिवाशीष प्रहराज, मध्य प्रदेश से अजीत पवार व दिल्ली से श्रेया सिंह शामिल थे।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार, शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से 'नो डिटेन्शन' जैसी पॉलिसी को लागू कर जानबूझ कर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिराने की कोशिश कर रही है। सरकारी स्कूलों की कमी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, मौलिक सुविधाओं का अभाव, पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं की कमी जैसी बुनियादी समस्याओं के कारण पढ़ने और पढ़ाने के माहौल को ही खत्म कर दिया गया है। इस नीति को लागू किए जाने से छात्रों में पढ़ाई के प्रति बची-खुची उन्मुखता को भी खत्म किया जा रहा है। सरकार, इस नीति को लाने के घोषित उद्देश्य, जो छात्रों में परीक्षा के दबाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं और स्कूल ड्रॉपआउट्स में आ रही बढ़ोतरी को रोकना था, में नाकाम साबित हुई। हमारे संगठन द्वारा लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के दबाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने इस नीति को दुबारा से जाँचने का सुझाव भी दिया। मगर अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस-नीत यू.पी.ए. सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया। मौजूदा भाजपा-नीत राजग सरकार ने इस पर सोच विचार करने में 3 वर्ष से भी ज्यादा लगा दिए और इन 3 वर्षों के बाद नतीजा निकला भी तो मात्र आंशिक सुधार जिसके तहत अभी शिक्षा का अधिकार कानून-2009 में एक सुधार लाने की बात की गई है जिसमें 5वीं व 8वीं कक्षा में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे इन कक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों की दुबारा परीक्षा लेकर, परीक्षा परिणाम के आधार पर दुबारा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को, चाहे तो, रोकने की नीति बना सकते हैं। हालांकि इस आंशिक जीत पर एआईडीएसओ ने छात्रों व संघर्षशील शिक्षाप्रेमी जनता को बधाई दी लेकिन साथ ही कक्षा-1 से पास-फेल प्रणाली पुन: लागू करने के लिए आंदोलन तेज करने की अपील भी की।

पुणे में दलित युवक की हत्या की एसयूसीआई(सी) ने की घोर निंदा

ऐसी जातिवादी-साम्प्रदायिक हत्याओं और हिंसा की पुनरावर्ति रोकने के लिए विवेकशील लोगों से एकजुट होने का आह्वान

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 4 जनवरी 2018 को जारी किये एक बयान में कहा : पुणे में हुई दलित समुदाय के युवक की हत्या की हम तीव्र निंदा करते हैं जब उच्च वर्ण के लोगों और दलित समुदाय के लोगों के बीच पुणे, मुम्बई और इनसे लगते हुए इलाकों में 1 जनवरी को टकराव हो गया था। अभी हाल ही में तथाकथित गोरक्षा, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन और ऐसे ही अन्य इस या उस बहाने दबे-पिसे दलितों, मुस्लिमों के साथ-साथ ईसाइयों को प्रताड़ित करने, उन पर हमले करने और यहां तक कि पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर मामलों में घोर साम्प्रदायिक आरएसएस-बीजेपी-संघ परिवार और उनकी मदद प्राप्त ग्रुप संलिप्त पाये गए हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं बीजेपी और इसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में हो रही हैं जिसमें सरकारी तंत्र चाहे सीधे शामिल न भी हो, पर ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति मूकदर्शक बना रहता है। क्योंकि आरएसएस-बीजेपी का एजेण्डा ही है साम्प्रदायिक-जातिवादी खाई को और भी चौड़ा करना ताकि मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ा जा सके और शासक पूंजीवाद द्वारा पैदा की जा रही जीवन की ज्वलंत समस्याओं से उनका ध्यान भटकाया जा सके।

दलितों पर होने वाले हमलों की तुरंत रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग के साथ ही हम सही सोच रखने वाले जनवाद पसन्द लोगों का आह्वान करते हैं कि वे आरएसएस-बीजेपी सरकार द्वारा बार-बार भड़काये जा रहे ऐसे साम्प्रदायिक-जातिवादी झगड़ों के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद में उठ खड़े हों और सचेत सशक्त जनवादी आन्दोलनों और वैचारिक संघर्षों के जरिए ऐसी हत्याओं और हिंसा की पुनरावर्ति को रोकने के लिए एकजुट हों।

काकोरी के शहीद ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

इस मौके पर एसयूसीआई के जिला सचिव ओमप्रकाश व किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान बलबीर सिंह ने सभा को संबोधित किया। भिवानी, दिनोद और तिगड़ाना में 17, 18 व 19 दिसम्बर को सभाएं की गई। भिवानी में हलवास गेट पर हुई सभा को एसयूसीआई(सी) के लोकल सचिव कॉ. राजकुमार जांगड़ा, दिनोद में एआईडीवाईओ के राजेश ने और तिगड़ाना में ऑल इण्डिया डीवाईओ के जिला सचिव सन्दीप मेहरा ने सम्बोधित किया।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication : January 5, 2018

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 से 21 जनवरी, 2018

केरल में साम्राज्यवाद–विरोधी कन्वेंशन

एर्नाकुलम: सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. के. श्रीधर

एर्नाकुलम। 20 दिसंबर को अखिल भारतीय साम्राज्यवाद–विरोधी फोरम (एआईएआईएफ) केरल चेप्टर के तत्वावधान में स्थानीय अचुथा मेनन हाल में साम्राज्यवाद–विरोधी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता एआईएआईएफ के केरल चेप्टर के उपाध्यक्ष प्रो. के. अरविंदाक्षन ने की और ए.आई.ए.आई.एफ. के एक राष्ट्रीय नेता के. श्रीधर ने इसका उद्घाटन किया। डॉ. वी. वेणुगोपाल, एडवोकेट मैथ्यूव वेलांगदन, प्रो. विन्सेन्ट मलीक्केल, जी.एस. पदमकुमार, के. के. गोपी नायर, ए. शेखर और टी.के. सुधीर कुमार अन्य वक्ता थे।

सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व जनमत की घोर उपेक्षा कर अमेरिका के साम्राज्यवादियों द्वारा यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दिये जाने की भर्त्सना की गई। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के इस सबसे घृणित कृत्य की निष्पक्षतापूर्वक निंदा करने के लिए भारत सरकार की झिझक का भी प्रस्ताव में दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया।

अपने उद्घाटन संबोधन में के. श्रीधर ने कहा कि समाजवादी खेमे के ढह जाने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों की अगुआई वाले साम्राज्यवादी खेमे की ओर से विश्वशांति के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया है। आज दुनिया में, विशेष रूप से मध्य पूर्व में विनाशकारी युद्ध और शरणार्थी संकट युद्धखोर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा सृजन किया हुआ है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में घोषित किया जाना अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा जारी हमलों की कड़ी में ताजातरीन है। मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवादियों के आपराधिक सहयोगी जियोनिस्ट इजरायल के पक्ष में अमेरिका की इस कार्रवाई ने इस क्षेत्र में तनाव को आगे बढ़ा दिया है और फिलिस्तीनियों की दुर्दशा बढ़ा दी है। उन्होंने सभी स्वतंत्रताप्रिय लोगों को साम्राज्यवादी मनसूबों के खिलाफ जोरदार साम्राज्यवाद–विरोधी आंदोलन गठित करने के लिए आगे आने का आह्वान किया।

शिक्षा बचाओ कमेटी ने किया संसद मार्च

नई दिल्ली। कक्षा–1 से पास–फेल प्रणाली दुबारा लागू करने की मांग पर 2 जनवरी को ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी ने संसद मार्च किया जिसमें छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों ने हिस्सा लिया। यह मार्च मंडी हाऊस से शुरू होकर बाराखम्बा रोड व टॉलस्टाय मार्ग होते हुए संसद मार्ग पर पहुंचकर विरोध सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता सेव एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने की। सभा को म. प्र. से डॉ. रामवतार शर्मा, पंजाब से अमरीन्दर पाल सिंह ग्रेवाल, हरियाणा से हरीश कुमार सैनी, उ. प्र. से डॉ. नरेन्द्र सिंह, दिल्ली से श्रीमती शारदा दीक्षित, श्रीमती शुभा दीक्षित ने संबोधित किया। सभा का संचालन संगठन के दिल्ली राज्य सचिव गिरवर सिंह ने किया। एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया।

बजट-पूर्व बैठक में मजदूरों के दिये गए सुझावों का बजट में नहीं होता कोई प्रतिफलन

5 दिसम्बर को नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों से बजटपूर्व चर्चा के लिए मुलाकात की। असल में हर साल रिवाज की तरह होने वाली ये मीटिंगें जनतांत्रिक व्यवस्था का मुखौटा खोल कर रख देती हैं। ट्रेड यूनियन नेतृत्व मजदूर वर्ग की जिन ज्वलंत मांगों को साल दर साल रखता आ रहा है, वास्तव में उनकी तरफ तवज्जों नहीं दी जा रही है।

एआईयूटीयूसी की तरफ से इस मीटिंग में प्रतिनिधित्व संगठन के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने किया। उन्होंने कहा कि हर साल ही वित्तमंत्री बजटपूर्व मीटिंग बुलाते हैं। ट्रेड यूनियन नेतृत्व के वक्तव्य बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बजट में उनका कोई प्रतिफलन नहीं मिलता है। देश की लगाातार बिगड़ती आर्थिक हालत के प्रसंग में उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक संकट प्रतिदिन गहरे से गहरा होता जा रहा है। इसके नतीजतन आम मेहनतकश लोगों की जिन्दगी और रोजी–रोटी का सबसे ज्यादा नुकसान होता जा रहा है।

विश्व भूख सूचकांक के मुताबिक भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या वाली सूची में भारत का स्थान 118 देशों में से 100वां है। विकास के खाते में केन्द्रीय सरकार अक्सर ही बजट आवंटन देती रहती है, लेकिन असल में विकास का हाल क्या है ये आंकड़े उसकी झलक हैं। 120 करोड़ आबादी वाले देश भारत में 23 करोड़ लोग भूख मिटाने के लिए दो जून खाना नहीं जुटा पाते हैं। आये साल 1 करोड़ लोग लम्बे अर्से तक भूखे रहने के कारण कुपोषण जनित रोगों से मारे जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हरे–भरे इस देश में हर 10 सैकण्ड में भूख की आग में एक आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। सामाजिक–आर्थिक सेन्सस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत के 49 प्रतिशत परिवार सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अनियमित शारीरिक श्रम के जरिये जीवन यापन करते हैं। 6.68 प्रतिशत परिवार भिखारी हैं और 4.08 प्रतिशत परिवारों का गुजर बसर का साधन है कागज और दूसरी रद्दी चुगना अर्थात् जो कागज चुगने वालों के नाम से जाने जाते हैं। इस देश के खेतीबाड़ी करने वालों के प्रसंग में कॉमरेड साहा ने कहा कि इस दौरान कर्ज के बोझ तले दब कर देश के 3 लाख से भी ज्यादा किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को मजबूर हुए हैं। बीजेपी शासनकाल में गत दो सालों में किसानों की आत्महत्याओं में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कॉमरेड साहा ने सारे भारत के आधार पर पंचवर्षीय कार्यसंस्थान/बेरोजगारी की समीक्षा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 77 प्रतिशत परिवारों की कोई भी नियमित कमाई नहीं है अर्थात् परिवार में तन्ख्वाह या वेतन या नियमित पारिश्रमिक पाने वाला कोई सदस्य नहीं है। 15 से 29 साल की उम्र के 30 प्रतिशत से ज्यादा नौजवानों को कोई काम नहीं है या वे किसी भी शिक्षण संस्था या प्रशिक्षण केन्द्र से जुड़े हुए नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चपरासी के 368 पदों के लिए 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिनमें एमए पास और पीएचडी किये हुए प्रार्थी भी हैं।

बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की बेहद कमी और रोजगारहीनता वर्तमान में किस मुकाम पर पहुंच गई है और इस मामले में बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र के वादे बिल्कुल झूठे निकले इस विषय में कॉमरेड साहा ने कहा कि 2017 के जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ इन चार महीनों में 15 लाख रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। नोटबंदी का यह बेलगाम नतीजा है। भारत के सबसे बड़े मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन की एक समीक्षा में उभर कर आये तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि नोटबंदी के 34 दिन में छोटे और मझौले उद्योगों में 35 प्रतिशत नौकरी कम हो गई हैं और 50 प्रतिशत राजस्व घट गया है। मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन की एक और समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2017 के मार्च महीने में 60 प्रतिशत रोजगार के अवसर घटेंगे और राजस्व 55 प्रतिशत घटेगा।

2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में यह घोषणा की थी कि सत्ता में आये तो वे हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। इस प्रसंग में कॉमरेड साहा ने कहा कि हमारे देश में 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इनको नौकरी देने का सपना दिखाया गया। लेकिन 2015 में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ 1.55 लाख और 2016 में यह 2.31 लाख तक ही पहुंच पाया। उधर रोजगार खत्म करने की संख्या 15 लाख है।

कॉमरेड शंकर साहा ने यह भी कहा कि जब लोग भोजन के अभाव में मर जाते हैं, करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं, लगातार बढ़ती महंगाई की मार से लोगों को रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे जिन्दा रहने का उपाय ढूंढ़े, तब विभिन्न व्यक्तियों की विशाल मूर्तियां लगाने, तेज चलने वाली बुलैट ट्रेन चलाने की व्यवस्था करने का क्या कोई तुक बनता है? गैर–निस्पादित परिसंपत्तियों अर्थात् अदा नहीं किये गए बैंक कर्ज के प्रसंग में उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़े–बड़े कारपोरेट घरानों द्वारा लेकर नहीं दिये गए कर्ज की मात्रा 11 लाख करोड़ पार कर कर गई है तब सरकार इन कारपोरेट घरानों के कर्ज क्यों माफ कर रही है? बैंकों को सरकारी खजाने से भारी मात्रा में पैसा देकर उनकी पूंजी का घाटा पूरा कर रही है? कर्ज न चुकाने वाले डिफाल्टर कारपोरेट घरानों को नये सिरे से कर्ज क्यों दे रही है? किस तरह गौतम अडाणी जैसे उद्योगपति जिनका इस बीच बैंक से लिये गए कर्ज की मात्रा 96,000 करोड़ रुपये है, उन्हें आस्ट्रेलिया में उनकी खान परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का मौका मिला है।

इस बजट–पूर्व मीटिंग में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक बार फिर मजदूर–कर्मचारियों के जीवन की मूल मांगें पेश की। इनमें कुछ महत्वपूर्ण मांगें हैं–सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाये, टैक्स चोरी करने वालों और कर्ज डिफाल्टरों के खिलाफ कारगर कदम उठाये जायें, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक किया जाये, उपयुक्त रोजगार के अवसरों के लिए पर्याप्त कोष की व्यवस्था की जाये, स्थायी कामों में नियुक्त ठेका और कैज्यूअल वर्करों को स्थायी कर्मचारी की मान्यता दी जाये, केन्द्रीय राष्ट्रीकृत संस्थाओं में विनिवेशीकरण बंद किया जाये इत्यादि।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com** फोन नं. : 011-25726631, 9868350503